



## **ONGC News, 12.12.2021 Print**

# ग्राहकों के लिए छलावा है कच्चे तेल का सस्ता होना

कूड कीमत में 17% की गिरावट पर भी कंपनियों ने नहीं दिया फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी तेल कंपनियों ने फिर साबित कर दिया है कि उन्हें तेल कीमत निर्धारित करने की छूट सिर्फ ग्राहकों पर बोझ डालने के लिए मिली है। पूरे अक्टूबर में रोजाना करीब 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि का बोझ आम जनता पर डालने वाली इन कंपनियों ने नवंबर में एकदम चुप्पी साध ली, जबकि कच्चे तेल (कूड आयल) के दाम में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट हुई। अब कूड फिर महंगा होने की राह पर है और डालर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है तो आम जनता के सामने फिर पेट्रोल व डीजल के महंगा होने की तलवार लटक गई है। पहले भी यह देखा गया है कि जब कूड महंगा होता है तो उसका बोझ तुरंत ग्राहकों पर डाल दिया जाता है, जबकि उसके सस्ता होने पर ग्राहकों को राहत देने में



कूड में फिर तेजी का रुख, रुपया कमजोर होने से भी असर बढ़ा ● फाइल फोटो

कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती है।

केंद्र सरकार ने चार नवंबर को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की थी। उसके बाद कई राज्यों ने भी इन उत्पादों पर स्थानीय स्तर पर लागू वेट दरों में भी खासी कटौती की है। लेकिन उस कटौती के बाद कूड की कीमतों में जो कमी हुई, उसका कोई फायदा ग्राहकों को नहीं दिया गया। आठ नवंबर को कच्चे तेल का भाव

84.18 डालर प्रति बैरल पर गया था, जो 15 नवंबर को 70.50 डालर प्रति बैरल रह गया। इसके बाद लगभग पूरे महीने यह इसी कीमत के आसपास रहा, जो आठ नवंबर के मुकाबले 17 प्रतिशत कम था। लेकिन इस कमी का ग्राहकों को कोई फायदा नहीं मिला। और इसके बाद इसमें तेजी से वृद्धि का रुख बना। अब कूड की कीमतों में वृद्धि के नए सिरे से संकेत मिलने लगे हैं। इसकी कीमत इस सप्ताह शुक्रवार को 74.42 डालर थी। फिर, अब तो डालर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है और रुपये का यह बदलता भाव पेट्रो उत्पादों की कीमत तय करने में अहम होता है। माना जाता है कि डालर के मुकाबले रुपये में हर 100 पैसे की कमी पेट्रोल का घरेलू दाम 40 पैसे और डीजल का 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ा देती है।